

न्यायालय जिला कलक्टर, बारां ( राजस्थान )

पीठासीन अधिकारी- श्री नरेन्द्र गुप्ता आई०ए०एस०

प्रकरण संख्या- 9/2008

बउनवान

1. गट्टू बाई आयु 73 वर्ष पत्नि श्री मूलीलाल
2. मदनलाल आयु 49 वर्ष पुत्र श्री मूलीलाल
3. कृष्णमुरारी आयु 27 वर्ष पुत्र श्री मदनलाल जातिगण मालव धाकड निवासीगण अन्ता तहसील अन्ता जिला बारां (राज०) (प्रार्थीगण)

बनाम

1. एन.टी.पी.सी (नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड) जयें प्रबन्धक एन.टी.पी.सी. अन्ता जिला बारां (राज०)
2. उप प्रबन्धक (कार्मिक एवं प्रशासनिक) एन.टी.पी.सी. अन्ता
3. भूमि अवाप्ति अधिकारी, उप जिला कलक्टर, बारां
4. भूमि अवाप्ति अधिकारी (एन.टी.पी.सी.) अन्ता चंबल परियोजना नवीन भवन जिलाधीश कार्यालय कोटा, जिला कोटा
5. राजस्थान सरकार जयें तहसीलदार अन्ता, तहसील अन्ता, जिला बारां (राज०)(अप्रार्थीगण)

रेफरेन्स प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा-18 भूमि अवाप्ति अधिनियम

- उपस्थिति :- 1.श्री ओम भारद्वाज अभिभाषक  
2. श्री रमेश चन्द गोयल अभिभाषक

(प्रार्थीगण)  
(अप्रार्थीगण)

आदेश दिनांक- 11.01.2023

प्रार्थीगण ने जयें अभिभाषक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि माल चक शाहबाद तहसील अन्ता में आराजी खसरा नंबर 35 रकबा 7 बीघा 15 बिस्वा भूमि प्रार्थीया के 1/2 हिस्से पर खातेदारी दर्ज है। अप्रार्थी क्रम 1 को अपना प्रोजेक्ट एन.टी.पी.सी. स्थापित करने के लिए प्रार्थीया की उक्त वर्णित भूमि की आवश्यकता हुई तथा सन् 1986 में अन्य भूमियों के साथ जयें अधिसूचना अप्रार्थीगण ने प्रार्थीया की भूमि भी अवाप्त कर ली तथा जयें नोटिस दिनांक 17.04.1989 प्रार्थी को सूचना प्रेषित कर दी कि खसरा नंबर 35 अवाप्त कर ली गई है। वक्त अधिग्रहण राजस्व रेकार्ड में अधिग्रहित भूमि पर रघुनाथ का नाम दर्ज था जिनका स्वर्गवास दिनांक 17.04.1989 से पूर्व हो चुका था। उक्त भूमि रघुनाथ की खातेदारी की थी, प्रार्थीया क्रम 1 ने रघुनाथ की खातेदारी को गलत बताकर विवादित भूमि पर खातेदारी अधिकार प्राप्त करने हेतु अधिग्रहण से पूर्व सन् 1979 में सक्षम राजस्व विभाग न्यायालय एस.डी.ओ. बारां में वाद संख्या 144/89 गट्टू बाई बनाम गोमदी वगैरह पेश किया हुआ था जिसका निर्णय दिनांक 28.03.2001 को होकर प्रार्थीया को 1/2 हिस्से पर खातेदारी दर्ज करने के आदेश /डिक्री जारी की। उक्त भूमि की एक मात्र खातेदार प्रार्थीया की माता धन्नीबाई थी तथा धन्नीबाई का निधन दिनांक 07.02.1974 को प्रार्थीया क्रम 1 के पक्ष में जयें रजिस्टर्ड दानपत्र प्रार्थीया को उक्त खसरा नंबर 35 माल चक शाहाबाद सहित अन्य कृषि भूमि मकान प्रार्थीया को दान कर कब्जा दे दिया। प्रार्थीया की अधिग्रहित भूमि का मुआवजा अप्रार्थीगण ने मात्र 6000 /- रुपये प्रतिबीघा नियत करते हुए

जिला कलक्टर  
बारां (राज०)



परिवार के एक सदस्य को अपनी सेवा में स्थायी नियोजन देने का प्रस्ताव किया है जो अपर्याप्त है। चक शाहाबाद की वर्तमान बाजार दर एक लाख रूपये प्रतिबीघा से कम नहीं है, अधिग्रहित भूमि पर्याप्त पानी, अत्याधिक उपजाऊ चंबल की दाईं नहर से सिंचित होने से तथा सड़क से लगवा होने से आबादी विस्तार होने से उपयोगी होने से भारी कीमत रखती है। अप्रार्थीगण ने अन्य किसानों को 70000/- रूपये से मुआवजा राशि का भुगतान किया है। प्रार्थीया एक लाख रूपया प्रतिबीघा की दर से मुआवजा राशि प्राप्त करने का अधिकार रखती है। प्रार्थीगण अप्रार्थीगण से आजीविका के लिये नियमित नियोजन पाने के अधिकारी हैं। प्रार्थीयागण ने समय समय पर अप्रार्थीगण को इस हेतु आवेदन किये हैं किन्तु कोई सुनवाई नहीं हुयी। प्रार्थीगण ने दिनांक 14.03.2002 को आवेदन किया तथा दिनांक 14.03.2002 रजिस्टर्ड नोटिस दिया इसके बावजूद कोई कार्यवाही नहीं की। बिना मुआवजा भुगतान ही अप्रार्थीगण के नाम जर्ज इन्तकाल नंबर 116 दिनांक 31.05.2002 से एन.टी.पी.सी अन्ता के नाम दर्ज हो गयी। प्रार्थीगण ने अवाप्त शुदा भूमि का मुआवजा प्राप्त करने के लिए सक्षम आवेदन अप्रार्थी संख्या 3 को प्रस्तुत किया जिसे सुनवाई हेतु स्वीकार कर लिया तथा दिनांक 27.07.2006 को भूमि अवाप्ति अधिकारी चंबल परियोजना कोटा से रिकार्ड तलब करने के आदेश पारित किये तथा आदेश दिनांक 27.10.2006 से जिला कलक्टर, बारां से मार्गदर्शन चाहा था, परन्तु बिना मार्गदर्शन के ही पत्रावली आदेश दिनांक 17.02.2007 से प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र इस आदेश के साथ निरस्त कर दिया कि प्रस्तुत प्रार्थना पत्र इस न्यायालय के क्षेत्राधिकार का नहीं होने से कार्यवाही ड्रॉप की जाती है तथा प्रार्थीगण को निर्देश दिये गये कि तत्कालीन भूमि अवाप्ति अधिकारी कोटा को चाराजोही हेतु प्रार्थना पत्र पेश करें। वक्त अधिग्रहण बारां उपखण्ड कोटा जिले का अंग था। एन.टी.पी.सी अन्ता के लिए अधिग्रहण मुआवजा आदि की पश्चावर्ती सभी कार्यवाही अप्रार्थी संख्या 3 द्वारा सम्पादित की गई है। अधिग्रहित भूमि खसरा नंबर 35 रकबा 7 बीघा 15 बिस्वा के वर्तमान खसरा नंबर 86 रकबा 1.16 है। माल चक शाहाबाद अन्ता सिंचित एवं उपजाऊ है, प्रार्थीगण की आजीविका का आधार है। जिसकी अवाप्ति के समय बाजार दर 70,000/- रूपया प्रतिबीघा थी तथा वर्तमान में एक लाख रूपया प्रतिबीघा है। प्रार्थीगण दीवानी अदालत से अधिग्रहण राशि निर्धारित करवाने हेतु प्रकरण को न्यायालय जिला जजी बारां को भिजवाए जाने (रिफर) करने की प्रार्थना करते हैं। प्रार्थीगण ने अधिग्रहित भूमि की मुआवजा राशि प्राप्त नहीं की है। पूर्व में अन्य किसी न्यायालय में कार्यवाही प्रस्तुत नहीं की है। अतः आवेदन प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थीगण की अधिग्रहित भूमि अवार्ड संख्या ए.एन.जी./पी.पी./ए. एण्ड एन./3049 दिनांक 17.04.1989 बाबत खसरा नंबर 35 रकबा 7 बीघा 15 बिस्वा वर्तमान खसरा नंबर 86 रकबा 1.16 है। बाबत तय मुआवजा को न्यायोचित निर्धारण हेतु अन्तर्गत धारा 18 भूमि अवाप्ति अधिनियम जिला जजी बारां को भिजवाया जाकर अधिग्रहित भूमि का मुआवजा एक लाख रूपया प्रतिबीघा सहित परिवार के एक सदस्य को सुनिश्चित रोजगार दिलवाये जाने का आदेश फरमावे।



*[Handwritten Signature]*  
**जिला कलक्टर  
 बारां (राज०)**

प्रार्थना पत्र पेश होने पर नियमानुसार दर्ज रजिस्टर कर, अप्रार्थीगण को तथा अधीनस्थ न्यायालय का रेकार्ड तलब किया गया। अप्रार्थीगण क्रम 1 व 2 की ओर से जर्ज अभिभाषक जवाब इस आशय का पेश हुआ कि विवादित वर्णित कृषि भूमि एन.टी.पी.सी. अन्ता के खाते में दर्ज है। सन् 1986 में राजस्थान सरकार ने भूमि अवाप्ति अधिनियम के अन्तर्गत भारत सरकार के उपक्रम एन.टी.पी.सी की स्थापनार्थ भूमि अवाप्ति के लिये अधिसूचना जारी की थी, उक्त भूमि अवाप्त किए जाने हेतु प्रार्थीयागण को अलग से कोई सूचना प्रेषित नहीं की क्योंकि भूमि अवाप्ति अधिनियम के तहत भूमि अवाप्ति का नोटिफिकेशन जारी होने के बाद भूमि अवाप्ति की समस्त कार्यवाही भूमि अवाप्ति अधिकारी द्वारा की जाती है। भूमि अवाप्ति अधिकारी ने जारी

अधिसूचना की तारीख को भूमि विशेष का बाजारू मूल्य के आधार पर मुआवजा तय कर अवाई जारी किया था। प्रार्थीगण का यह कथन नितान्त असत्य है कि प्रार्थिया के परिवार के एक सदस्य को अपनी सेवा में स्थायी नियोजन देने का प्रस्ताव भी किया था। यदि प्रार्थिया का तथाकथित जमीन में किसी प्रकार का स्वत्व या हित था तो उसके लिये प्रार्थिया को भूमि अवाप्ति अधिकारी के समक्ष अपनी आपत्ति प्रस्तुत करनी चाहिये थी एवं जारी अवाई से यदि वह असंतुष्ट थी तो उक्त आदेश पारित होने के 6 माह के अंदर अंदर एवाई को चुनौती देते हुए उसके खिलाफ दफा 18 भूमि अवाप्ति अधिनियम के अंतर्गत कार्यवाही जिला कलक्टर के समक्ष प्रस्तुत की जा सकती है। चूंकि यह कार्यवाही अंदर मियाद प्रस्तुत नहीं हुई है। इसलिए निरस्त योग्य है। प्रार्थिया के स्वत्व हित का निर्णय करने का अधिकार भूमि अवाप्ति अधिकारी को था। प्रार्थिया का यह कर्तव्य था कि वे भूमि अवाप्ति अधिकारी के समक्ष प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर उक्त कार्यवाही में भूमि अवाप्ति अधिनियम के अंतर्गत अपनी आपत्तियां प्रस्तुत करने हेतु पक्षकार बनती एवं अपनी आपत्तियां भूमि अवाप्ति अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करती परन्तु उन्होंने भूमि अवाप्ति की कार्यवाही के दौरान इस प्रकार की कोई आपत्ति प्रस्तुत नहीं की। प्रार्थिया अवाप्तशुदा भूमि की वह क्षति राशि ही प्राप्त करने की अधिकारणी है जो धारा-4 भूमि अवाप्ति अधिनियम के तहत जारी अधिसूचना की तारीख को थी। अतः प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत रेफरेंस प्रार्थना पत्र खारिज फरमाया जावे। अप्रार्थीगण की ओर से जवाब पेश होने पर प्रकरण बहस हेतु नियत किया गया।

बहस के दौरान अभिभाषक प्रार्थीगण ने लिखित बहस इस आशय की पेश की कि वाके माल चक शाहाबाद में आराजी खसरा नंबर 35 रकबा 7 बीघा 15 बिस्वा आराजी को सन् 1986 में अन्य भूमियों के साथ जर्ज अधिसूचना द्वारा नोटिस दिनांक 17.04.1989 को प्रार्थियागण को सूचना प्रेषित की कि खसरा नंबर 35 अवाप्त कर ली है। प्रार्थियागण की पैतृक सम्पत्ति के पूर्व खातेदार रघुनाथ पुत्र नाथू के नाम राजस्व रेकार्ड में दर्ज थी तथा भूमि अवाप्ति अधिकारी द्वारा भूमि अवाप्ति के सम्बन्ध में धारा 9(1)(3) का एक नोटिस दिनांक 24.04.1986 को रेस्ट हाउस अंता में उपस्थित होने हेतु प्रेषित किया उस नोटिस के पृष्ठभाग पर गजानंद सहना की रिपोर्ट में अंकित किया गया कि रघुनाथ फोट हो गया है तथा उनकी पोती संतोषबाई को तामील करवाने के बाद तामील दिनांक 13.04.1986 को पेश की। इस प्रकार यह तथ्य प्रमाणित है कि अधिग्रहण के पूर्व ही खातेदार रघुनाथ की मृत्यु हो चुकी थी। तत्पश्चात दिनांक 17.04.1989 को एनटीपीसी द्वारा दिनांक 17.04.1989 को एक पत्र क्रमांक ए.एन.जी.पी.पी./पावर/3041 द्वारा रघुनाथ पुत्र नाथू के नाम से जारी किया जिसमें चक शाहाबाद की आराजी खसरा नंबर 35 रकबा 7 बीघा 15 बिस्वा को अवाप्त करने की जानकारी की गई तथा उक्त पत्र में यह भी उल्लेखित किया कि आप स्वयं को या स्वयं के परिवार के सदस्य को रोजगार प्रदान करने हेतु वांछित दस्तावेजों के साथ दिनांक 24.04.1989 को परियोजना कार्यालय में उपस्थित होने हेतु उप प्रबंधक (कार्मिक एवं प्रशासन) अरविन्द जैन द्वारा जारी किया गया। उक्त आराजी के संबंध में हक व हिस्से के निर्धारण हेतु राजस्व प्रकरण विचाराधीन होने से उक्त आराजी का मुआवजा किसी भी पक्ष द्वारा प्रार्थीगण को नहीं दिया गया। सम्बन्धित मुकदमा संख्या 144/89 का निस्तारण दिनांक 28.03.2001 से न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बारां ने प्रार्थियागण के मध्य 1/2, 1/2 आराजी के हक अधिकार की घोषणा की गई तथा दिनांक 18.12.2003 को विभाजन की डिक्री जारी की गई, जिसमें स्पष्ट स्प से उल्लेखित है कि प्रार्थीगण चक शाहाबाद तहसील अन्ता की आराजी खसरा नंबर 35 रकबा 7 बीघा 15 बिस्वा की आराजी का मुआवजा प्रार्थीगण आधा आधा रखेगे, तत्पश्चात प्रार्थीगण द्वारा प्रार्थना पत्र एस.डी.ओ. साहब बारां के यहां मुआवजा दिलाये जाने हेतु प्रस्तुत किया जिसे एस.डी.ओ. द्वारा वर्ष 2004 में दर्ज कर दिनांक 17.12.2007



*[Handwritten signature]*  
जिला कलक्टर  
बारां (राज.)

को सक्षम अधिकारिता का नही होने के कारण उक्त पत्रावली को ड्रॉप कर दिया तथा इसके बाद प्रार्थीगण द्वारा धारा 18 भूमि अवाप्ति अधिनियम की कार्यवाही न्यायालय जिला कलक्टर, बारां में पेश की है। उपरोक्त विवादित आराजियात के जेरकार वाद रहते हुये उपरोक्त आराजी का बिना मुआवजा अदा किये एन.टी.पी.सी. के पक्ष में बिना जांच किये नामान्तकरण संख्या 116 तस्दीक किया गया है। प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत रेफरेन्स कार्यवाही के अन्तर्गत न्यायालय जिला कलक्टर, बारां चक शाहाबाद तहसील अंता की आराजी खसरा नंबर 35 रकबा 7 बीघा 15 बीस्वा से संबंधित अवार्ड की पत्रावली तलबी हेतु कई प्रयास के बावजूद भी अवार्ड प्राप्त नही हुआ तथा कार्यालय भूमि अवाप्ति अधिकारी, बारां द्वारा दिनांक 27.09.2021 को एक रिपोर्ट पेश की जिसमें वांछनीय रिकार्ड तलाश करने हेतु नायब तहसीलदार श्री हेमन्त बामनिया को भूमि अवाप्ति अधिकारी कोटा के यहां भेजकर रेकार्ड ढूंढा गया लेकिन रेकार्ड वहां जमा नही होना बताया। तथा एन.टी.पी.सी. अन्ता द्वारा भी अपने पास उक्त अवार्ड से संबंधित कोई जानकारी होना नही बताया जिससे स्पष्ट हो जाता है कि उक्त भूमि का अवार्ड बना ही नही तथा बिना अवार्ड पारित किये ही प्रार्थीगण की आराजी का अधिग्रहण कर लिया जिससे प्रार्थीगण के साम्पत्तिक अधिकारों का हनन हुआ है। जेरकार पत्रावली के पेज नंबर 259 पर पत्रांक 240 दिनांक 12.04.1988 से धारा 6 व 17(4) की लिस्ट मांगी गई जिसमें जिन खातेदारों की भूमि ली गई थी ओर एक सूची मांगी गई जिन खातेदारों का देहान्त हो चुका है तथा उनको मुआवजा प्राप्त हो गया है उक्त लिस्ट में तत्कालीन खातेदार रघुनाथ का नाम मृतक व्यक्तियों की सूची में शामिल नही किया तथा पत्रावली के पेज नंबर 263 पर दिनांक 21.05.1988 को एन.टी.पी.सी. द्वारा खसरा नंबर व व्यक्तियों के नाम की सूची प्रमाणीकरण के लिये मांगी गई जिसमें चक शाहाबाद की आराजी खसरा नंबर 35 रकबा 7 बीघा 15 बिस्वा का ना तो मुआवजा बताया ओर न ही अवार्ड नंबर का उल्लेख किया गया इसी प्रकार पेज नंबर 277 दिनांक 18.07.1988 के पत्र में यह तथ्य स्पष्ट रूप से उल्लेखित किया गया कि स्थगन व रेफरेन्स व जेरकार वाद से संबंधित राशि की मांग भूमि अवाप्ति अधिकारी द्वारा एन.टी.पी.सी. से नही की गई है तथा उक्त प्रकरणों के निस्तारण होने के पश्चात विवादित आराजियात की राशि की मांग की जावेगी। इस प्रकार न तो चक शाहाबाद की आराजी खसरा नंबर 35 रकबा 7 बीघा 15 बिस्वा का कोई अवार्ड पारित हुआ और न ही उसका मुआवजा दिया गया। भूमि अधिग्रहण अधिनियम की धारा 9 के अन्तर्गत भूमि अवाप्ति अधिकारी संबंधित व्यक्तियों को अधिग्रहण से संबंधित आपत्ति हेतु नोटिस जारी करेगा, प्रस्तुत प्रकरण में धारा 6 का जो नोटिस रघुनाथ पुत्र नाथू को जारी किया गया था उसके पृष्ठ भाग पर दिनांक 13.04.1986 पर स्पष्ट रूप से रघुनाथ के फोट होने का अंकन किया गया था उक्त तथ्य की जानकारी होने के बावजूद भी भूमि अवाप्ति अधिकारी द्वारा मृतक व्यक्ति को ही धारा 9 के अन्तर्गत नोटिस जारी किया जो विधि विरुद्ध जारी किया गया। तत्पश्चात धारा 11 के अन्तर्गत भूमि अवाप्ति अधिकारी (कलक्टर) समस्त पक्षकारों को आपत्ति पर सुनवाई का अवसर प्रदान करेगा तथा उसका निस्तारण करने के बाद अवार्ड जारी करेगा प्रस्तुत प्रकरण में मृतक व्यक्ति के विरुद्ध समस्त कार्यवाहीयां निष्पादित की गई जो शून्य है। उक्त प्रकरण में कलक्टर/भूमि अवाप्ति अधिकारी द्वारा भूमि अवाप्ति अधिनियम की धारा 12(2) के अन्तर्गत व्यथित पक्षकारों को नही सुना गया जबकि विधि का यह सुस्थापित सिद्धान्त है कि पक्षकारों की सुनवाई के पश्चात ही अवार्ड जारी होगा। प्रस्तुत प्रकरण में भूमि अवाप्ति अधिनियम के समस्त विधिक प्रावधानों की अनदेखी कर प्रार्थीगण के महत्वपूर्ण व मूल्यावान साम्पत्तिक अधिकारों का हनन किया गया है, तथा उक्त अधिग्रहण में गंभीर कानूनी अनियमितताये स्पष्ट रूप से परलक्षित है जिसके निर्धारण हेतु उपरोक्त प्रकरण को जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय बारां के यहां रेफरेन्स करने का आदेश फरमावें।



*ol*  
जिला कलक्टर  
बारां (राज.)

अप्रार्थीगण क्रम 1 व 2 की ओर से जयें अभिभाषक लिखित बहस का जवाब इस आशय का पेश हुआ कि प्रार्थीया ने दिनांक 28.05.2007 या उसके आस पास कार्यवाही माननीय जिला जज साहब बारां के यहां Refer कराने हेतु पेश की है। प्रार्थीगण की अधिग्रहित भूमि अवार्ड दिनांक 17.04.1989 बाबत खसरा नंबर 35 रकबा 7 बीघा 15 बिस्वा वर्तमान खसरा नंबर 86 रकबा 1.16 है। बाबत मुआवजा निर्धारित को न्यायोचित निर्धारण हेतु जिला जज साहब बारां को भिजवाया जावे। Refer किया जावे। अधिग्रहित भूमि का एक लाख रूपया प्रतिबीघा निर्धारित किया जावे व परिवार के सदस्य को रोजगार दिलाया जावे। प्रार्थना में यह भी अंकित किया है कि मुआवजा राशि 6000/- रूपये प्रतिबीघा निर्धारित की है, अन्य को 70,000/- रूपये प्रतिबीघा दी है। अवार्ड की सूचना भी प्रार्थीया को दिनांक 17.04.1989 से दिया जाना अंकित किया है। इस प्रार्थना पत्र का जवाब एनटीपीसी अन्ता द्वारा प्रस्तुत किया गया। कार्यवाही अवधि मध्य प्रस्तुत नहीं हुई इसलिए Refer नहीं की जा सकती है। धारा 18 भूमि अवाप्ति अधिनियम "18(1) Any person interest who has not accepted the award may, by written application to the collector, require that the matter be refferred by the collector for the determination of the court whether his objection be to the measurment of the land the amount of the compensation the persons to whom it is payable, or the apportionment of the comoensation among the persons interested.

(2) The application shall state the grounds on which objection to thhe award is taken: Provided that every such applicant shall be made-

(a) if the person making it was present or represented before the Collector at the time when he made his awarded, within six weeks from the date of the Collector's awarded  
(b) in other cases within six weeks of the receipt of the notice from the Collector under section 12, sub-section (2) or within six months from the date of the Collector's award whichever period shall first expire"

उक्त प्रावधानों के अनुसार Refer कराने के लिए लिखित में आवेदन अधिकतम अवार्ड की तारीख से 6 माह के अन्दर अन्दर पेश किया जाना आवश्यक है। प्रार्थी ने अवार्ड दिनांक 17.04.1989 को Refer कराने के लिए दिनांक 28.05.2007 या उसके आस पास लिखित प्रार्थना पत्र पेश किया है जो अवधि मध्य पेश नहीं किया गया है। अवधि मध्य कार्यवाही पेश नहीं होने पर कलक्टर साहब को Refer करने का अधिकार नहीं है। इस संबंध में माननीय सुप्रीम कोर्ट का निर्णय 1996 DNJ S.C. 88 प्रस्तुत है। Land Acquisition Act, 1894-Secs. 4,6&11- Power of courts under- Power to condone delay in filing reference against award-Award made in presence of parties.- Reference made after expiry of prescribed 6 weeks limitation- High Court condoned the delay constructing the Acquisition Officer as Court under the code of Civil procedure- Whether justified ? -Held, No, the authority acting as Acquisiton officer cannot be constructed as Court as such provision of limitation Act cannot be applied while making referrence.

Land Acquisition Act, 1894- Secs. 18(1), 18(2) provision and 29(2) and Limitation Act-Secs.5- Powers of Collector for extending period of limitation- while exercising Powers u/s 18(1) Whether delay can be condoned?- Held, No Since the Authority exercing power u/s. 18(1) is not the court withing the meaning of C.P.C. Sec. 5 Limitation Act cannot be applied for the extension of Limitation.



जिला कलक्टर  
बारां (राज.)

इससे स्पष्ट है कि कार्यवाही यदि अवधि मध्य प्रस्तुत नहीं हुई हो तो Refer नहीं की जा सकती है। इस कार्यवाही को करते समय जिला कलक्टर को कोर्ट के अधिकार नहीं होते हैं। धारा 5 भी लागू नहीं होती है। इसलिए यह कार्यवाही मियाद में पेश नहीं होने से खारिज होने योग्य है। इस कार्यवाही में लिखित बहस में अवार्ड की वैधानिकता या अवार्ड जारी न होने बाबत जो भी आपत्तियां उठाई गई हैं वे सभी का निर्धारण करने का अधिकार कलक्टर को नहीं है। एनटीपीसी लिखित बहस में उठाई सभी आपत्तियों को स्वीकार नहीं करती है। प्रार्थना पत्र में प्रार्थी द्वारा अवार्ड जारी होने की सूचना प्रार्थीया को दिनांक 17.04.1989 को देना अंकित है। प्रार्थीया द्वारा अवार्ड राशि का भुगतान राजस्व वाद क्रमांक 144/89 गट्टूबाई बनाम गोमदी में स्टे कराना भी अपने प्रार्थना पत्र में अंकित किया है इससे भी स्पष्ट है कि प्रार्थीया को अवार्ड जारी होने की जानकारी थी। यदि अवार्ड राशि का भुगतान प्रार्थीया को प्राप्त नहीं हुआ हो तो वह भूमि अवाप्ति अधिकारी को मुआवजा प्राप्त करने का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर मुआवजा प्राप्त कर सकती थी। एनटीपीसी से सीधा भुगतान विधिनुसार प्राप्त नहीं किया जा सकता। एनटीपीसी अन्ता द्वारा भूमि अवाप्ति अधिकारी द्वारा जब भी मुआवजा मांगा गया, जमा किया है। एनटीपीसी के लिये 707 बीघा 17 बिस्वा भूमि अधिग्रहित की गई है जिसमें अन्ता की 68 बीघा 11 बिस्वा, चक शाहाबाद की 116 बीघा 17 बिस्वा, तामखेडा की 45 बीघा व ग्राम रातडिया की 477 बीघा 17 बिस्वा है। अधिग्रहण की कार्यवाही पहले भूमि अवाप्ति अधिकारी चम्बल प्रोजेक्ट कोटा के यहां चली तथा बारां जिला बनने के बाद एस0डी0ओ0 बारां के यहां चली है। यह कहना कि भूमि का रिकार्ड संबंधित अधिकारी को नहीं मिला, जिसके आधार पर यह मान लिया जावे कि भूमि अधिग्रहण नहीं हुई है गलत है क्योंकि 707 बीघा भूमि के अवाप्ति का रिकार्ड नहीं बना हो संभव नहीं है। राशि जो भूमि अवाप्ति अधिकारी एनटीपीसी मांगते थे व एनटीपीसी द्वारा जमा की जाती थी, उसका अंकन भूमि अवाप्ति अधिकारी की केश बुक में हुआ होगा। धारा 18 भूमि अवाप्ति अधिनियम के तहत कार्यवाही तभी होगी जब अवार्ड बना हो। भूमि अवाप्ति के लिए नियमानुसार धारा 4 व 6 के गजट नोटिफिकेशन में शाया हुए हैं। निर्धारित प्रक्रिया की पालना की जाकर अवार्ड धारा 11 व 12 में पारित किया गया है तथा धारा 16 में भूमि अवाप्ति अधिकारी द्वारा व कब्जा लिया गया व भूमि एनटीपीसी को दी है जिसका एनटीपीसी के हक में इंतकाल खुला है। धारा 18 भूमि अवाप्ति अधिनियम के तहत यदि कार्यवाही अवधि मध्य प्रस्तुत हो तभी जिला कलक्टर द्वारा धारा 18 में अंकित आपत्तियां भूमि नाप, मुआवजा व मुआवजा राशि का भुगतान किसे किया जावे तथा मुआवजा राशि का विभाजन कैसे किया जावे इस बाबत interested person द्वारा प्रस्तुत आपत्तियों का निर्धारण कराने के लिए रेफर जिला जज साहब को की जा सकती है। जिला कलक्टर को इस कार्यवाही में अवार्ड की वैधानिकता या अवार्ड जारी होने की प्रक्रिया की कमी का निर्धारण करने की अधिकारिता नहीं है। जिसके लिए प्रार्थीया को पृथक से दावा या अन्य कार्यवाही करनी चाहिए। अवार्ड नियमानुसार पूर्ण प्रक्रिया कर जारी किया गया है। कार्यवाही अवधि मध्य प्रस्तुत नहीं होने से खारिज की जावे।



जिला कलक्टर  
बारां (राज०)

हमने बहस उभयपक्ष विद्वान अभिभाषकगण की सुनी। दौराने बहस अभिभाषक प्रार्थियागण ने प्रार्थना पत्र एवं प्रस्तुत लिखित बहस में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि प्रार्थियागण के पिता के खाते की आराजी ग्राम चक शाहाबाद की आराजी खसरा नंबर 35 रकबा 7 बीघा 15 बिस्वा के अधिग्रहण की सूचना जर्ने नोटिस दिनांक 17.04.1989 प्रेषित कर उस पर अंकित तामील कुनिन्दा की रिपोर्ट "रघुनाथ फोट हो गया है तथा उनकी पोती संतोषबाई को तामील करवाने के बाद तामील पेश है" की अनदेखी कर बगैर भूमि का मुआवजा दिये अवाप्त कर ली। अधिग्रहण से पूर्व ही खातेदार रघुनाथ की मृत्यु हो चुकी थी। दिनांक 17.04.1989 को

एनटीपीसी द्वारा पत्र मृतक रघुनाथ पुत्र नाथू के नाम जारी किया गया तथा दिनांक 24.04.1989 को उपस्थित होने के निर्देश दिये। उक्त आराजीयात के संबंध में राजस्व प्रकरण विचाराधीन था जिसमें न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बारां ने दिनांक 28.03.2021 को निर्णय पारित कर प्रार्थियागण एवं गट्टूबाई के 1/2-1/2 हिस्से में दर्ज करने के आदेश प्रदान किये। नामान्तकरण संख्या 116 से उक्त भूमि एनटीपीसी के खाते दर्ज हो गई थी। प्रकरण में बार बार तलब किये जाने के उपरांत भी मूल अवार्ड प्राप्त नहीं हुआ। धारा 11 के अन्तर्गत भूमि अवाप्ति अधिकारी (कलक्टर) समस्त पक्षकारों को आपत्ति पर सुनवाई का अवसर प्रदान करेगा तथा उसका निस्तारण करने के बाद अवार्ड जारी करेगा प्रस्तुत प्रकरण में मृतक व्यक्ति के विरुद्ध समस्त कार्यवाहियां निष्पादित की गई जो शून्य है। उक्त प्रकरण में कलक्टर/भूमि अवाप्ति अधिकारी द्वारा भूमि अवाप्ति अधिनियम की धारा 12(2) के अन्तर्गत व्यथित पक्षकारों को नही सुना गया जबकि विधि का यह सुस्थापित सिद्धान्त है कि पक्षकारों की सुनवाई के पश्चात ही अवार्ड जारी होगा। प्रस्तुत प्रकरण में भूमि अवाप्ति अधिनियम के समस्त विधिक प्रावधानों की अनदेखी कर प्रार्थियागण के महत्वपूर्ण व मूल्यवान साम्प्रतिक अधिकारों का हनन किया गया है, तथा उक्त अधिग्रहण में गंभीर कानूनी अनियमितताये स्पष्ट रूप से परलक्षित है जिसके निर्धारण हेतु उपरोक्त प्रकरण को जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय बारां के यहां रेफरेन्स करने का आदेश फरमावें। अपने कथन के समर्थन में अभिभाषक प्रार्थियागण ने The Land Acquisition Act, 1894 की छायाप्रति पेश की।



दौराने बहस अभिभाषक अप्रार्थियागण ने जवाब रेफरेन्स एवं जवाब लिखित बहस में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि प्रार्थियागण का यह कथन नितान्त असत्य है कि अवार्ड जारी नहीं हुआ। प्रार्थियागण द्वारा प्रस्तुत रेफरेन्स कार्यवाही अवार्ड राशि को प्राप्त करने हेतु पेश नहीं की है बल्कि जिला जज को रेफर करने की प्रार्थना की है। प्रार्थियागण ने स्वयं रेफरेन्स में स्वीकार किया है कि मुआवजा 6000/- रुपये प्रतिबीघा तय किया गया जबकि भूमि की कीमत एक लाख रुपये बीघा है, तथा डीएलसी रेट से भुगतान बाबत अंकित किया है। प्रार्थियागण द्वारा मुआवजा बढ़ाने की प्रार्थना की गई। भूमि अवाप्ति अधिनियम की धारा 18 (2) (a) में अवार्ड के विरुद्ध कार्यवाही करने का समय निर्धारित है। प्रार्थियागण द्वारा प्रस्तुत कार्यवाही अवधि बाधित है। यदि अवार्ड गलत था तो प्रोपर टाईम में उचित स्थान पर चुनौती दी जानी चाहिये थी। प्रार्थियागण ने न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बारां में विचाराधीन वाद क्रमांक 144/89 बउनवान गट्टूबाई बनाम गोमदीबाई का निर्णय दिनांक 28.03.2001 को होना आवेदन में अंकित किया है तथा अवाप्तशुदा भूमि का मुआवजा प्राप्त करने हेतु उपखण्ड अधिकारी बारां को आवेदन वर्ष 2006 में प्रस्तुत करना अंकित किया है। प्रार्थियागण ने पांच वर्ष से अधिक समय पश्चात अवाप्तशुदा भूमि का मुआवजा प्राप्त करने हेतु उपखण्ड अधिकारी बारां को आवेदन पेश किया है जो तय समयावधि में पेश नहीं किया गया। जबकि अवाप्तशुदा भूमि बाबत जानकारी प्रार्थियागण को न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बारां में विचाराधीन वाद के समय ही थी तथा किसी भी पक्षकार को मुआवजा भुगतान नहीं किये जाने बाबत आवेदन तत्समय उपखण्ड अधिकारी बारां को किया जाना स्वयं प्रार्थियागण ने आवेदन में अंकित किया है। अतः प्रार्थियागण का आवेदन निरस्त फरमाया जावे। अपने कथन के समर्थन में अभिभाषक अप्रार्थियागण ने विधिक दृष्टांत 1996 डीएनजे (एससी) 88 बउनवान द ऑफिसर ऑन स्पेशल ड्यूटी व अन्य बनाम शाह मनीलाल चन्दुलाल वगैरह में पारित निर्णय दिनांक 09.02.1996 की छायाप्रति पेश की।

जिला कलक्टर  
बारां (राज.)

हमने बहस उभयपक्ष पर मनन किया। सम्पूर्ण पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। प्रार्थियागण द्वारा अपने प्रार्थना पत्र में अवाप्त भूमि की मुआवजा राशि 6000/- रुपये प्रतिबीघा की दर से तय किया जाना बताया है तथा उक्त मुआवजा नगण्य होने से मुआवजे के न्यायोचित निर्धारण हेतु धारा 18 भूमि अवाप्ति अधिनियम के तहत जला जज, बारां को रेफर करने की प्रार्थना की है। परन्तु मुआवजा निर्धारण प्रार्थियागण द्वारा किस आधार पर कम माना गया है इसका कोई आधार नहीं बताया है। प्रस्तुत लिखित बहस में प्रार्थियागण के अभिभाषक द्वारा अंकित किया गया कि भूमि का अवार्ड बना ही नहीं तथा बिना अवार्ड ही भूमि का अधिग्रहण कर लिया, जबकि अपने प्रार्थना पत्र में उनके द्वारा यह माना गया है कि अवाप्त भूमि की मुआवजा राशि 6000/- रुपये प्रति बीघा की दर से तय की गई थी। विद्वान अभिभाषक अप्रार्थी का यह कथन सही है कि अवार्ड जारी होने के 6 सप्ताह के अन्दर रेफरेन्स प्रार्थियागण को पेश करना चाहिये था जबकि अवार्ड दिनांक 17.04.1989 के पश्चात यह रेफरेन्स 30.05.2007 को 6 वर्ष की अवधि पश्चात पेश किया गया है। अभिभाषक अप्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत विधिक दृष्टांत 1996 डीएनजे (एससी) 88 के अनुसार Land Acquisition Act, 1894- Sec 18(1),18(2) Proviso and 29(2) and Limitation Act- Sec. 5- Powers of Collector for extending period of limitation – While exercising Powers u/s. 1/4 Powers u/s 18(1) is not the Court within the meaning of C.P.C., Sec. 5 Limitation Act cannot be applied for extension of limitation. यह प्रकरण 6 वर्ष बाद प्रार्थियागण द्वारा पेश किया गया है। अतः delay condon नहीं की जा सकती है। भूमि अवाप्ति अधिनियम, 1894 की धारा 18 (1) के अनुसार Any person interest who has not accepted the award may, by written application to the collector, require that the matter be referred by the collector for the determination of the court whether his objection be to the measurement of the land, the amount of the compensation the persons to whom it is payable, or the apportionment of the compensation among the persons interested. इस न्यायालय द्वारा अवार्ड की वैधानिकता तथा अवार्ड जारी होने की प्रक्रिया की कमी का निर्धारण करने की अधिकारिता नहीं है।

अतः उपरोक्त विवेचन अनुसार प्रार्थियागण द्वारा प्रस्तुत रेफरेन्स प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है। प्रार्थियागण को यदि अवार्ड राशि प्राप्त नहीं हुई हो तो वह सक्षम भूमि अवाप्ति अधिकारी के यहां चाराजोही कर सकती हैं।

आदेश आज दिनांक 11.01.2023 को लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।



(नरेन्द्र गुप्ता)  
जिला कलेक्टर, बारां  
बारां (राज०)